

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 72

प्रभाव

बीकानेर, शनिवार 4 अक्टूबर, 2025

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

“आई लव मोहम्मद” अभियान के विरोध या समर्थन का कोई असर नहीं दिख रहा है बिहार के चुनाव में

यह इस बात की पुष्टि करता है कि सदा से ही बिहार की राजनीति में धर्म से ज्यादा जाति असरदार है

–श्रीनंद झा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। क्या उत्तर प्रदेश का ‘आई लव मुहम्मद’ अभियान भाजपा द्वारा इस तरह रचा गया था कि बिहार में चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा सके?

इसी तरह की कई साजिश की थ्योरी सामने आ रही हैं, खासकर बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी और उनके, उनके सहयोगियों व परिवार पर जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद।

बिहार की राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति का कोई बड़ा असर अब तक नहीं पड़ा है। यहाँ धर्म से अधिक, जाति ही राजनीतिक पहचान का मुख्य आधार रही है। लेकिन अतीत में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक ध्ववीकरण ने भाजपा को चुनावी लाभ जरूर दिया है।

पिछले महीने कानपुर में अल्पसंख्यकों पर पुलिस की कार्रवाई

■ जैसा कि विदित है कि मौलाना तौकीर रजा खान ने गत माह आई लव मोहम्मद अभियान शुरु किया था, जो महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात में भी पहुँचा।

■ इसके जवाब में हिन्दुवादी ग्रुप्स ने “आई लव महादेव”, “आई लव राम” पोस्टर वॉर छेड़ा। राजनीति टीकाकारों के अनुसार, इन दोनों अभियानों का ज्यादा असर इसलिये नहीं हुआ, क्योंकि तौकीर रजा खान को यू.पी. का असदुद्दीन ओवैसी समझा जाता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का कर अपने वक्तव्यों से ध्रुवीकरण करते हैं और इसका फायदा भाजपा को ही मिलता है।

■ यह भी कहा जाता है कि मौलाना तौकीर रजा खान बरेली के भाजपा नेता संतोष गंगवार के नजदीकी हैं और एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने ही जेल से रिहाई के लिए उनकी जमानत की व्यवस्था कराई थी।

■ बिहार के सीमांचल क्षेत्र में, जहाँ मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में हैं, जरूर ओवैसी की पार्टी को, जो सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि वे मौलाना के पक्ष में अच्छी खासी बयानबाजी कर रहे हैं।

और ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर लगाने वालों पर रोक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। मौलाना तौकीर रजा खान ने इनका नेतृत्व किया, जिसके चलते

आंदोलन महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात तक फैल गया। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने ‘आई लव महादेव’, ‘आई लव राम’ और यहाँ तक कि ‘आई

लव बुलडोजर’ जैसे पोस्टरों के साथ मुहिम छेड़ दी।

इस पोस्टर राजनीति ने माहौल को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया

जयपुर, 03 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस माह दीपावली के त्यौहार से पहले राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि का उपहार दिया है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि देय होगी।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का

■ राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 25 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।

अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत देय होगी।

इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मिक एवं 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढोतरी का फायदा मिलेगा।

पुतिन ने मोदी को साहसी नेता बताया

सोची, 03 अक्टूबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत किसी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

पुतिन ने काला सागर के तट पर स्थित रूस के सोची शहर में आयोजित वाल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के मंच पर बोलते हुए कहा, “भारत और चीन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।” रूसी राष्ट्रपति का इशारा हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत आयात

■ उन्होंने कहा अब भारत पुराना भारत नहीं, अब वो किसी तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।

शुल्क लगाने और रूस से तेल आयात बंद नहीं करने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले की ओर था।

रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को साहसी नेता बताया और कहा कि, “भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, अब वो किसी तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।” पुतिन ने कहा, “अगर भारत रूस से तेल आयात बंद कर देता है तो इसे बहुत घाटा होगा। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर जानते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक रूस की सीमा से लगते देश ही “आतंकित” थे रूस की आक्रामक कार्यवाही से

पर, अब रूस ने ड्रोन की उड़ानों से व एयर स्पेस उल्लंघन से मध्य यूरोप को भी डराना शुरु कर दिया है

■ सबसे पहले ये ड्रोन की उड़ानें पोलैण्ड में देखी गई थीं। इसके बाद कोपनहेगन, डैनमार्क, एस्टोनिया में भी हुई हैं।

■ इन उड़ानों से कई जगह एयरपोर्ट उड़ाने विलंबित हुई हैं। ऐसी घटना दो साल पूर्व हुई थी, जिसमें नॉथ सी में गैस पाइपलाइन को दुर्घटनाग्रस्त किया गया था।

■ लंदन की बहुप्रतिष्ठित पत्रिका इकॉनमिस्ट ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारी आपसी बातचीतों के बावजूद भी अभी तक रूस के खिलाफ कॉमन फ्रंट बनाकर खड़े होने की क्षमता नहीं बनी है। यूरोप को यह भी भय है कि अगर अभी रूस की डराने वाली कार्यवाही नहीं रोकी गई तो रूस की हिम्मत बढ़ती जायेगी। कुछ रूसी भाषी अल्पसंख्यकों की सहायता से वो रूस पर अपना आधिपत्य बढ़ाता जाएगा।

वजह से बंद करना पड़ा। इसके बाद डेनमार्क का बिजनेस एयरपोर्ट भी आसपास ड्रोन उड़ानों से प्रभावित हुआ। एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक उड़ान भरते हुए देखे गए।

ड्रोन के अलावा, यूरोप में जरूरी

सेवाओं को बाधित करने वाली घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। करीब दो साल पहले उत्तरी सागर में एक बड़ी गैस पाइपलाइन को समुद्र की सतह के नीचे क्षतिग्रस्त पाया गया।

सभी आरोपों की उंगली रूस की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एयर चीफ मार्शल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को हराया भारत ने

एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा, पूरी दुनिया ने भारतीय वायु सेना की ताकत देखी

■ उन्होंने बताया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों के साथ एक “अर्ली वॉरिंग एण्ड कंट्रोल प्लेन” नष्ट किया था और यही नहीं अमेरिका में बने सी-130 विमान, जिसे “हरक्वुलिस” कहा जाता है, को भी नष्ट किया है।

■ सिंह ने बताया, “अर्ली वॉरिंग एण्ड कंट्रोल प्लेन” को 300 किलोमीटर दूर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया, जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का निशाना है।

■ उन्होंने कहा, हमारे हर हमले के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। पर, पाकिस्तान जो भारतीय राफेल गिराने के जो दावे कर रहा है, वह सिर्फ झूठा प्रचार है, जो वह अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए कर रहा है।

हमलों ने पाकिस्तानी रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रनवे, हैंगार

उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि सी-130 क्लास का एक अमेरिकी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान, जिसे “हक्वूलिस” कहा जाता है, वह भी निशाना बना हो।

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के नुकसान की बात करें तो हमने उनके कई एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और दो रनवे क्षतिग्रस्त हुए। तीन विभिन्न एयरबेस पर तीन हैंगर भी नष्ट हुए,” उन्होंने कहा।

एयर चीफ ने बताया कि एक एईडब्ल्यू एण्ड सी या इलैक्ट्रॉनिक इन्टेलिजेंस विमान को 300 किलोमीटर से अधिक दूरी से निशाना बनाकर मार गिराया गया, जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का सतह से हवा में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दो साल तक के बच्चों के कफ सिरप ना दें’

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत की रिपोर्टों को देखते हुए, केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीचएएस) ने दो

■ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राजस्थान व मध्यप्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई छोटे बच्चों की मौतों के मद्देनज़र यह निर्देश दिया।

साल तक के बच्चों को कफ सिरप न देने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय की ओर से शुक्रवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को जारी परामर्श में कहा है कि बच्चों में आम तौर से होने वाली खांसी अपने-आप ठीक हो जाती है और किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। उसने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी और खांसी की दवा नहीं दी जानी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनम वांगचुक की रिहाई के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अंगमो ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

■ वांगचुक की पत्नी की याचिका पर दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी।

गुरुवार को दायर कर अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

उन्होंने अपनी याचिका में अपने पति पर एनएसए लगाने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी "गिरफ्तारी अवैध और नियमों का उल्लंघन है।" उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनके पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया।

गौरतलब है कि वांगचुक राजस्थान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के शटडाउन का असर धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों और जनता को महसूस होने लगा

केन्द्रीय सरकार के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को अगले सप्ताह पे चैक नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी बचत भुनाकर रोज़मर्रा का खर्चा चलाना पड़ेगा

तक, कई कर्मचारियों को अपना पहला वेतन नहीं मिल पाएगा, जिससे परिवारों को अपनी बचत को खर्च करना पड़ेगा या कर्ज़ लेना पड़ सकता है।

इस शटडाउन के प्रभाव पहले ही दिखने लगे हैं। हवाई यातायात यूनियनों ने स्ट्राफ की कमी को लेकर चेतावनी दी है, जिससे उड़ानों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और कई सार्वजनिक सेवाएं- जैसे पासपोर्ट कार्यालय और छोटे व्यवसायों के लिए लोन डेस्क आदि अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। सेवानिवृत्त नागरिकों, पूर्व सैनिकों और ग्रामीण इलाकों में सरकारी सहायता पर निर्भर परिवारों के लिए यह शटडाउन पहले से ही कठिन आर्थिक स्थिति में मुश्किले बढ़ा रहा है।

इस बार का संकट पहले के शटडाउन की तुलना में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वाइट हाउस की ओर से स्थायी

■ जब तक बजट प्रस्ताव सीनेट से पारित नहीं होता, बिना तनख्वाह के छुट्टी पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व सैनिक व ग्रामीण परिवार, जो सरकारी मदद पर निर्भर हैं, उनके जीवन में आर्थिक तनाव और बढ़ जायेगा।

■ साधारण नागरिक के लिए नैशनल पार्क, म्यूजियम व अन्य पब्लिक सेवाएँ, यहाँ तक कि एयरपोर्ट व हवाई सेवा भी सुरक्षाकर्मियों के अभाव में अस्त-व्यस्त होनी शुरु हो गई है।

छंटनी के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रेस सचिव कैसेलीन लेविट ने कहा कि एजेंसियां अब यह समीक्षा कर रही हैं कि “कहां-कहां छंटनी सन्निकट है,” जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि कई कर्मचारी अब अपनी नौकरियों पर वापस नहीं लौट पाएंगे।

सरकार इस फंडिंग अवरोध का इस्तेमाल अपने खर्च प्राथमिकताओं नया रुप देने के लिए कर रही है। ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि वह स्वच्छ

ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बंद कर रहा है- खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित राज्यों में। वहीं, परिवहन विभाग ने न्यूयॉर्क के लिए 18 अरब के इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स को फ्रीज कर दिया है। आलोकितों ने इन फैसलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है।

यह गतिरोध हैल्थकेयर फंडिंग सीनेट डेमोक्रेट्स कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडी बढ़ाना चाहते हैं, जबकि रिपब्लिकन किसी भी

विफलता की एक कड़वी याद दिलाता है। रोज़मर्रा की सुविधाएं – जैसे परमिट रिन्यू कराना या राष्ट्रीय उद्यानों की सैर – अब बंद हैं। जिन संघीय कर्मचारियों की जिंदगी महीने की तनख्वाह पर टिकी है, उनके लिए यह स्थिति बेहद कठिन है। वॉशिंगटन में घूमने आए एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने कहा, जो आज कई अमेरिकियों की साझा भावना बन गई है।

“समझौता किया जाता है। रास्ते निकाले जाते हैं। सबको थोड़ा-थोड़ा पीछे हटना पड़ता है।”

जहां रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पर यह आरोप लगा रहे है कि वे नीति-निर्धारण के लिए सरकार को बंधक बना रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स जवाब दे रहे हैं कि ट्रंप की सार्वजनिक सेवाओं में की जा रही आक्रामक कटौतियां समाजिक सुरक्षा तंत्र को खतरे में डाल रही है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)